sea limits are not demarcated or defined, some arrangements should be made so that fisherman either of Gujarat or of Pakistan may be guided not to cross into the sea waters of other countries. On both sides it is seen that innocent persons *i.e.* fishermen are being arrested and put in jails and facing trails. Their fishing vessels are being confiscated. Under these circumstances Government of India should take up this issue with the Pakistani Government and tackle this problem in a suitable manner. The Government of India is also requested to release the arrested fishermen who are presently detained in Pakistani jails. There are at present more than 200 persons detained in Pakistani jails.

Non-release of funds for the implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Madhya Pradesh

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मद में आवंटित 500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को प्रदान नहीं करने से वहां काफी समस्या उत्पन्न हो गई है। महोदय, उक्त राशि न केवल पूर्व से ही स्वीकृत थी बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने योजना आयोग से राज्य की आवश्यकता के अनुसार इसे 750 करोड़ करने की मांग की थी। महोदय, गांवों का विकास केन्द्र सरकार की प्राथमिकता है, वहीं ग्रामीण सड़क योजना के मद में स्वीकृत राशि को रोकने से न सिर्फ गांवों में सड़कों का निर्माण बाधित हुआ है बल्कि ग्रामीण युवकों को रोजगार से भी वंचित होना पड़ा है। महोदय, संतुलित क्षेत्रीय विकास केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है एवं इस में भेदभाव से क्षेत्रीय असंतुलन एवं पिछड़ापन बढ़ता है।

अत: सरकार से मेरी यह पुरजोर मांग है कि मध्य प्रदेश के विकास हेतु स्वीकृत राशि शीघ्र जारी की जाए। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि राज्यों के समुचित विकास में केन्द्र की अहम भूमिका होती है एवं सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मध्य प्रदेश को उस के हक की राशि मिले, यह सरकार का उत्तरदायित्व है। आशा है, सरकार इसे गंभीरता से लेगी।

SHORT DURATION DISCUSSION

Situation Arising out of the Price rise in the country

डा० मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए सदन के समक्ष उपस्थित हूं। हमने यह अनुरोध किया था कि यदि इस पर नियम 167 के अंतर्गत चर्चा हो तो वह उत्तम रहेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे साफ-साफ यह पता लग

जाएगा कि आम आदमी के साथ कौन है, मंहगाई घटाने के पक्ष में कौन है और मंहगाई बढ़ाने के पक्ष में कौन है? हमारे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के मित्रों को, देश को, इस बारे में साफ-साफ पता लगना चाहिए कि कौन मंहगाई के साथ है और कौन मंहगाई के विरुद्ध है? वाम फ्रंट के जो हमारे मित्र हैं, वे धमकियां बहुत देते हैं। बाहर कुछ कहते हैं, अन्दर कुछ कहते हैं। कभी-कभी मुझे उनके लिए उर्दू का एक शेर याद आ जाता है कि:-

साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं,

खूब परदा है, चिलमन से लगे बैठे हैं।

कुछ पता नहीं चलता कि किधर हैं, किधर नहीं हैं। यहां हैं या वहां हैं। मंहगाई की तरफ हैं या मंहगाई के खिलाफ हैं। यह परिस्थिति है। हम इसीलिए बहस चाहते थे कि यह मामला साफ होना चाहिए, देश के सामने तस्वीर साफ होनी चाहिए कि कौन किधर है? क्या चाहता है? अब वित्त मंत्री की नीतियां बहुत साफ-साफ हैं। वे बताते हैं कि जो उन्हें करना है उसको कहते हैं।

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): We are in our own position.

डा० मुरली मनोहर जोशी: वे एक स्पष्ट बात बोल रहे हैं और वह करना चाहते हैं। मगर इधर से दबाव पड़ता है तो वे भी नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि वे सी०एम०पी० और सी०पी०एम० के बीच में दो स्टूलों पर सवार हो जाते हैं। इसलिए आज की जो देश की परिस्थिति है, वह इसी का नतीजा है कि साफ नीतियां होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि सरकार किस रफ्तार से किधर जाना चाहती है, वह भी देश देख ले। उसके क्या अच्छे-बुरे परिणाम होंगे, उसे भी देश देख ले। अगर उन नीतियों में तब्दीली करनी है, सी०पी०एम० की नीतियों की तरफ जाना है, तो देश उसको भी देख ले कि किधर क्या होगा? लेकिन कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि जब हम देखते हैं कि सी०पी०एम० के हमारे दोस्त अन्दर तो जाकर डिनर खाते हैं और बाहर जाकर कुछ रैलियां करते हैं। अकबर इलाहाबादी ने ऐसे ही मौकों के लिए कहा था कि-

कौम के गम में डिनर खाते हैं, सरकार के साथ,

दर्द सी०पी०एम० को बहुत हैं मगर आराम के साथ। (व्यवधान)

देखिए वह दर्द बोल रहा है। (व्यवधान)

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी (मध्य प्रदेश): अकबर इलाहाबादी के साथ तरमीम मुबारक हो आपको।

†[مولانا عبیداللہ خان اعظمی: اکبرالہ آبادی کے ساتھ ترمیم مبارک ہو آپ کو۔]

---

†Transliteration in Urdu Script.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: बात यह है उपसभापति जी कि मैं खुद इलाहाबाद से हूं इसलिए थोड़ी-बहुत तरमीम करने का हक रखता हूं। खैर, तो मैं यह अर्ज कर रहा था, निवेदन कर रहा था कि सारी सरकार की नीतियां अगर एक साथ हों, बिलकुल स्पष्ट हों और उसमें किसी तरह का उलझाव, भटकाव न हो तो देश को समझने में बिल्कुल पूरे तौर पर सहूलियत होगी कि हम किधर जा रहे हैं और किधर को जाना ठीक है या गलत? अब आज के हालात क्या हैं, इस पर थोड़ा सा पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं। पिछले दिनों स्टेट्समैन अखबार में इस बारे में एक टिप्पणी निकली थी, जिसमें कहा गया था कि आदमी अब महंगाई में जन्म लेगा क्योंकि डॉक्टरों के दाम बढ़ गए हैं, ऊपर से सर्विस टैक्स और लग गया है, दवाइयों के दाम बढ़ने वाले हैं। अब लोग यह कहते हैं कि भले आदमी, तुम यह अक्तूबर, नवम्बर में क्यों पैदा हो रहे हो, फरवरी, मार्च में क्यों पैदा नहीं हो गए, जिससे तुम्हारे जन्म का खर्चा कुछ सस्ता होता। फिर उसके बाद अगर उसके पिता जी कार से उसको लाने, ले जाने या अस्पताल में देखने के लिए आते हैं, तो वह कहता है कि भले आदमी, कहां तुम पैदा हो गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बार-बार कार से आना मुश्किल है और अगर बस से आएं-जाएं, तो उसके भी दाम बढ़ गए हैं, उस तरह भी मुश्किल है। फिर पानी के दाम भी बढ़ गए, चार गुना हो गए दिल्ली में और अलग-अलग कैटेगराइजेशन हो गया, किसी को किसी दाम पर पानी मिलेगा, किसी को किसी दाम पर।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: पानी सिर से ऊंचा हो गया है।

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی: پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: जी हां। अभी आप उसी में बैठे हुए हैं, कम से कम अब तो बाहर निकल आइए। पानी सिर से ऊंचा जा रहा है, यह सही बात है। पानी का दाम बढ़ गया। उसके बाद कपड़ों के दाम बढ़ रहे हैं। उसको क्या पहनाएं? अब अगर वह ऐसा कहे कि अच्छा महंगाई है, तो मैं दुनिया से ही रुखसत होना चाहता हूं, आपको महंगाई की वजह से तकलीफ हैं उस हाल में भी क्रिमिटोरियम में दाम बढ़ गए हैं, दो सौ रुपए से चार सौ रुपए यहां दिल्ली में टैक्स हो गया है। इसका मतलब आपका जन्म लेना भी मुश्किल है महंगाई की वजह से, आपका जिंदा रहना भी मुश्किल है महंगाई की वजह से और आपका मरना भी मुश्किल है इस महंगाई की वजह से। किसी जमाने में वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकार की नीति है-कर,मर,कर। कर में जन्म ले और मरने के बाद भी कर चुकाता रहे क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तो इस तरह आज के हालात पर यह टिप्पणी अखबारों में हो रही है। लोग इस महंगाई से परेशान हैं, उनका जीवन दूभर हो रहा है।

उपसभापति जी, अब मैं देखता हूं कि जो सरकार है, उसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (CMP) में एक बात कही गई थी-"The UPA Government will take effective and strong measures to control the price hike of essential commodities. Provisions

---

†Transliteration in Urdu Script.

to deal with speculators, etc., etc. will not be diluted in any case." यह सरकार का वचन है कि वह प्राइस हाइक कंट्रोल करने के लिए एफेक्टिव और स्ट्रॉंग मैजर्स लेगी। फिर यह भी कहा था, जहां तक मुझे याद है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो विवरण लिया गया था, उसके अंदर एक पैराग्राफ में कहा था- "Consistent with *the philosophy of reforms with a human face, the burden of fiscal correc*tion will be shared more by those who can afford to do so. The success of direct taxes reforms, initiated in 1997, suggests that the prospects for fiscal correction are quite bright." अभी मैं आपको बताउंगा कि यह जो बर्डन बढ़ा है फिसकल करक्शन का, वह किस तरह से अनइवेन है, किस तरह से असंतुलित है, किस तरह से विषम है। कुछ लोगों पर यह ज्यादा है और इत्तफाक से उन पर ज्यादा है, जो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने यह वायदा किया था कि 7 से 8 प्रतिशत विकास-दर रहेगी और यह भी कहा था कि पीने का पानी सबको मिलेगा, बिजली सबको मिलेगी। ये सारे लक्ष्य उन्होंने जो रखे थे, ये लक्ष्य आज महंगाई के कारण, वित्तीय कुप्रबंधन के कारण, क्योंकि यह महंगाई बहुत कुछ वित्तीय कुप्रबंधन के कारण भी है, जिसकी वजह से यह बढ़ रही है और आप लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। उस वक्त भी, जब बजट प्रस्ताव यहां आए थे और बजट पर बहस हुई थी, तो हमारी तरफ से कहा गया था कि यह बजट मुद्रा-विस्तार करेगा, It is an inflationary Budget. बार-बार सरकार को यह चेतावनी दी गई थी कि इसका आप नियमन नहीं कर सकेंगे। आपकी करों की पालिसी, करों की नीति ऐसी है, जिसका तत्काल परिणाम मुद्रा-विस्तार में होगा। यह बिल्कुल सच निकला और आज जो मुद्रा-विस्तार की स्थितियां हैं, वे मैं आपको थोड़ा सा, वैसे तो सदन में बार-बार आ चुकी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि जनवरी, 2004 में यह होलसेल प्राइस इन्डेक्स और कन्ज्युमर्स प्राइस इन्डेक्स 5.9 और 6.9 थे। और इनको हमने घटाया, फरवरी में ये 5.2 थे। फिर 27 मार्च को 4.6, दोनों 4.6 थे। 1 मई को भी 4.6, 4.6 थे। लेकिन जून में, इनके आते ही, ये 6 और 5.6 हो गए। यानी हम जब सरकार छोड़कर गए तो उस वक्त इन्फलेशन का रेट 4.6 था, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4.6 था और जून में एकदम, एक महीने के अंदर, यह 6 और 5.6 हो गया। फिर आप जानते हैं कि 7.86 हो गया, फिर 8.33 हो गया और अब भी सारी इन तमाम चीजों के प्रबंध की बात कही जाती है, वित्त मंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि वे कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यह 7 या 7 के ऊपर चल रहा है। एक प्वाइंट कभी नीचे आ गया, एक प्वाइंट कभी आगे बढ़ गया। कभी-कभी मुझे शक होता है कि जब तक यह सदन चल रहा है, तब तक यह 7,7.1 तक रहेगा और सदन की समाप्ति के बाद शायद फिर यह 8, 8.5 तक पहुंच जाएगा। इस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। यानी यह जो मुद्रा विस्तार है, यह काफी चिंताजनक स्थिति की तरफ जा रहा है। इससे महंगाई काफी तेजी से बढ़ेगी क्योंकि उसके जो कारण उन्होंने बताए हैं कि जिस वजह से मुद्रा विस्तार हो रहा है, उन कारणों

पर अभी तक कोई नियंत्रण नहीं हो पया है, उनका वे ठीक से विरोध नहीं कर पाए हैं। अब आप यह देखें कि उन्होंने यह कहा था कि इसका बोझ आम आदमी, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके ऊपर कम पड़ेगा और जो बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। अब आप यह देखें कि इस समय हाल क्या है? आम आदमी की चीजें क्या हैं? सब्जियां। सब्जियां 10 रुपए, 20 रुपए किलो हुआ करती थीं, अब 30 रुपए, 40 रुपए किलो हैं। आलू जो 4, 4.5 रुपये किलो होता था, अब 10, 12 रुपए हो गया है। मुझे कभी-कभी लगता है कि एक बार जब प्याज़ के दाम इसी तरह से बढ़े थे तो सरकार उलट गई थी, यह महंगाई अगर इसी तरह से बढ़ी तो शायद यह अकेला कारण होगा उसके लिए, क्योंकि यहां मैं जो आपके सहयोगियों का रुख देखता हूं, वह कहीं आपको परेशान न करे और आपको कहीं मुसीबत में न डाल दे, इसकी मुझे चिंता होती है। खाद्य तेल 600, 650 रुपए प्रति टिन मिलते थे, अब उसके स्थान पर वे 800 रुपए प्रति टिन हो गए हैं। सीमेंट 110 रुपए से 160 रुपए प्रति बोरी हो गया है। स्टील का तो कुछ कहना ही नहीं है, वह तो आसमान छू रहा है। उसके बारे में तो मेरे एक मित्र ने बताया कि उनका एक ड्राइवर था, उससे दो दिन पहले वे बात कर रहे थे तो ड्राइवर ने कहा कि साहब, बहुत पेरशानी है। मैंने दो कमरे बनाने के लिए इंतजाम किया था, लेकिन मेरा एक कमरा भी पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्टील के दाम बढ़ गए हैं, ईंटों के दाम बढ़ गए हैं और ईंटों के दाम बढ़ने का कारण यह था कि आपने कोयले के दाम में 16. 7 परसेंट की वृद्धि कर दी तो भट्ठे वालों ने ईंटों के दाम बढ़ा दिए। आप जो हाऊसिंग एक्टिविटीज़ ज्यादा कराना चाहते हैं, वे भी इससे धीरे-धीरे कम हो जाएंगी क्योंकि स्टील बढ़ गया, सीमेंट बढ़ गया, ईंटें बढ़ गईं और महंगाई की वजह से फिर वेजिस बढ़ते हैं। नतीजा यह है कि ये जितने भी कार्यक्रम हैं, मैंने एक उदाहरण दिया कि कैसा परिणाम उसका पड़ता है, इससे आप मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैंने देखा कि पिछले 9 महीनों में किन चीजों के दाम घटे हैं। कलर टी॰वी॰ के दाम 5 परसेंट घटे हैं, रेफ्रिजिरेटर्स के दाम 5 से 7 परसेंट तक घटे हैं, वाशिंग मशीन्स के दाम 5 से 7 परसेंट तक घटे हैं, माइक्रोवेव ओवन के दाम 20 परसेंट तक घटे हैं। अब मैं नहीं जानता कि कितने आम आदमी इन चीजों का प्रयोग करते हैं और कितने आम आदमी सब्जियों का, सीमेंट का, ईंट का, लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। यह थोड़ा समझने की बात है, देखने की बात है कि बोझ किस तरह से बढ़ रहा है या घट रहा है, किधर बढ़ रहा है, किधर घट रहा है। यह आपकी घोषित नीति के सर्वथा विरुद्ध हो रहा है कि वे चीजें, जिन्हें धनी लोग, धन-सम्पन्न लोग प्रयोग में लाते हैं, उनके दाम घटें और जो चीजें आम आदमी प्रयोग में लाते हैं, उनके दाम बढ़ें। तो जो आपकी घोषणाएं थीं, आप उनसे सर्वथा विपरीत गए हैं। फिर अभी, आपने कल ही एक पत्र पेश किया है कि लोक सभा के सामने, जिसमें आपने एक मध्यवर्षीय अनुशीलन किया है अपने सारे बजट की परफारमेंस का। उसके अनुसार फिस्कल डेफिसिट का जो आपका टारगेट था, वह 76,171 करोड़ का था, 6 महीने के अंदर ही उसका 59,551 करोड़ आप प्रयोग कर चुके हैं यानी इतना तो आपने कंज्यूम कर लिया है अब आगे छः महीने में अगर इसी रफ्तार से बढ़ा तो

आपका फिस्कल डेफिसिट कहां जाएगा, यह सोचने की बात है। आपका रेवेन्यू कलैक्शन 19.3 प्रतिशत हुआ है, जो कि उस समय आपका लक्ष्य था। रेवेन्यू डेफिसिट 62,906/- करोड़ रुपये हो गया है जो छः महीने में 82.6 प्रतिशत बजट लक्ष्य था। तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तथा रेवेन्यू कलैक्शन कम हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, तो अर्थव्यवस्था पर आप किस प्रकार नियंत्रण करेंगे, यह सवाल देश का आम आदमी आपसे पूछ रहा है?

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी) पीठासीन हुईं।]

हमने आपसे तब भी कहा था कि ये जो आपकी नीतियां हैं, ये मुद्रा विस्तार करेंगी। इसमें जो सबसे ज्यादा विस्तार आपने किया है, वह है सेवा कर से एवं जो आपने शिक्षा के नाम पर cess लगाया। इसमें आपने सेवा कर तो आठ प्रतिशत से दस प्रतिशत कर दिया किन्तु cess लगा दिया। आपने यह कहा था कि इस बार 14,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य आप सेवा कर से वसूली का रखेंगे जो पिछले साल से छः हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। आपने कहा था, अभी जो आपकी बजट की विशेषताएं रखीं गयी थीं उसमें अभी मैंने देखा कि आप 5,000 करोड़ रुपए पूरे वर्ष में वसूल करेंगे। इन 4000 से 5000 करोड़ रुपए तक आप जो शिक्षा पर cess लगा रहे हैं, यह आप पूरे तौर पर मिड डे मील और शिक्षा के लिए देंगे। किंतु अब मैंने जो आपका बजट एलोकेशन देखा, जिसे अभी तक आपने शायद बदला नहीं है, उसमें प्राथमिकता शिक्षा में, एम.डी.एम. में केवल 300 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। जो सर्वशिक्षा अभियान है, उसमें भी आपने लगभग 300 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। यानी, जो हमारा 5,219 करोड़ रुपए का प्रारम्भिक शिक्षा के लिए बजट था, उसे आपने बढ़ाकर केवल 5,750 करोड़ रुपये किया। तब यह जो 500 करोड़ रुपये आपने बढ़ाए और 5000 करोड़ रुपए वसूल किये, यहां पर क्या हुआ? ये मिसमैच क्या है? क्या यह वसूल हुआ है या नहीं हुआ है, और यदि हुआ तो उसे यहां क्यों नहीं दर्शाया गया है? यदि आप कहते थे कि उस समय अनुमान नहीं था, तो क्या इस समय आपने इसमें संशोधन किया है? मुझे बताया गया कि यह सारा पैसा शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मिड डे मील्स में जाएगा, किंतु मैं नहीं समझता कि आपने इस तरह की बात अभी तक की है। इस प्रकार, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या प्रबंधन कर रहे हैं? How are you managing it? आपने किन चीजों के लिए कहा था और किधर ले जा रहे हैं और आपने अर्थव्यवस्था की क्या दुर्दशा कर दी, यह जरा देखने और समझने की बात है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, केवल छोटी-छोटी बातें हैं ऐसा कह कर बात नहीं होनी चाहिए।

मुझे अब एक बात और समझ में आती है कि जब-जब कांग्रेस पार्टी का शासन आता है, तब-तब मुद्रा विस्तार होता है। आप पिछले सभी शासनों को देख लें। आप उसके लिए कारण तो बता सकते हैं कि इस कारण हुआ या उस कारण हुआ, लेकिन हुआ जरूर है। वह चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा हो या श्री राजीव गांधी का कार्यकाल रहा हो या फिर श्री पी॰वी॰ नरसिंह राव जी का कार्यकाल रहा हो। श्री नरसिंह राव जी के कार्यकाल में तो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी

उस समय माननीय वित्त मंत्री जी थे, तब मैंने देखा कि 1991 से 1996 तक 10.6 का ऐन्युअल ऐवरेज इन्फ्लेशन था, प्राइमरी का 11.3, फ्यूअल का 11.3, मैन्यूफैक्चर गुड्स का 10.11 यही घटकर 2001 से 2004 में 4.2, 3.8, 6.9 और 3.4 रह गया। इस प्रकार यह जो आप देख रहे हैं कि जब आप आते हैं तो मुद्रा विस्तार होता, महंगाई बढ़ती है, चीजों के दाम बढ़ते हैं और जब आपके अलावा हमारी सरकार आती है, उस वक्त चीजों के दाम घटते हैं महंगाई घटती है, इन्फ्लेशन की रफ्तार घटती है। श्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में भी हमेशा इन्फ्लेशन 9%-10% तो रहा ही है और एक बार तो शायद 16%-17% हो गया था। उसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इन्फ्लेशन 10% से नीचे कभी नहीं आया। इस प्रकार से आप हमेशा महंगाई को बढ़ाने वाले क्रिया-कलाप करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? या तो आप चुनाव में जिन लोगों का साथ लेते हैं बाद में उनके हित साधन करने के लिए करते हैं या आपको प्रबंधन नहीं आता या किन हितों का, किन स्वार्थों का आप साधन करते हैं। यह इसमें से बात समझ में नहीं आती कि क्यों बार-बार ऐसा हो रहा है। आपका एक चरित्र बन गया है महंगाई का। सारे देश को हमेशा महंगाई में झोंक देने का यह आपका एक विशेष उपक्रम रहा है। जहां तक मैंने देखा है, वित्त मंत्री महोदय पाइंट बाई पाइंट इंफ्लेशन रेट बताते रहते हैं। उस सब को देखा जा सकता है, लेकिन असली बात है औसत। साल भर में क्या रहा, 5 साल में क्या रहा, महीने में, हफ्ते में, हर रोज कुछ थोड़ी बहुत घटोतरी-बढ़ोतरी होती रहती है। एक हफ्ते में बढ़ गया, दूसरे हफ्ते में घट गया। लेकिन सवाल यह है कि औसत क्या रहा, सारे वर्ष भर में क्या रहा, 5 सालों में क्या रहा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को स्थिरता तब मिलती है जबकि कोई चीज औसतन 4 साल, 5 साल, 10 साल एक सी रहे और अगर आप उसमें हर रोज घटाएंगे-बढ़ाएंगे, कभी 10 हो गया, फिर घटकर 8 हो गया, फिर साढ़े आठ हो गया, फिर पौने आठ हो गया, तो यह चीज नहीं चलती। आप अगर व्यवस्थित करेंगे, स्टेब्लाइज्ड करेंगे, उसको स्थिर करेंगे तो व्यवस्था भी स्थिर होगी और विकास भी हो सकेगा। अब सवाल यह है कि जो मैं देखता हूं कि आपका एक्सप्लेनेशन क्या है कि यह क्यों हो रहा है? जहां तक मुझे याद है वित्त मंत्री महोदय और माननीय प्रधान मंत्री जी के भाषणों को सुनकर और अखबारों में पढ़कर कि आपके यहां इसके चार कारण बताए गए। एक तो वित्त मंत्री जी ने शब्द दिया है —पैट्रोफ्लेशन। मैं समझता हूं कि यह अच्छा शब्द है। जो मुद्रा विस्तार पैट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से होता है, वह कहते हैं कि यह तो हमारे बस का ही नहीं है, यह तो इंटरनेशनल भी हो रहा है। हम तो लाचार हैं इसके सामने, इसको तो हम कुछ कर ही नही सकते। अब मैंने आपको बताया कि पैट्रो फ्लेशन हमारे जमाने में भी थोड़ा बहुत हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े थे और उसके बावजूद भी हमने मुद्रा विस्तार को नियंत्रित किया। यह आप नहीं कह सकते कि हमने मुद्रा विस्तार को नियंत्रित नहीं किया और पैट्रो फ्लेशन का जितना प्रभाव हो सकता था, जिस हद तक उसे स्थानांतरित किया जा सकता था या किया जाना चाहिए था वह भी हमने किया। लेकिन कुल मिलाकर के महंगाई पर नियंत्रण किया और मुद्रा विस्तार नहीं होने दिया। कोई सवाल, कभी कोई चर्चा, कोई बहस जनता में किसी प्रकार का आक्रोश इस महंगाई के सवाल

पर नहीं उठ रहा था। चीजें सुलभ थीं और उचित मूल्यों पर मिल रही थीं। दूसरा कारण आपने ही बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मांगों के कारण स्टील, कोल, मैटल, इन सब के दाम बढ़े। हां स्टील वगैरह की मांग देश में भी बढ़ सकती है, क्योंकि हाऊसिंग को हमने काफी बढ़ाया है। लेकिन मुख्यतया आप कहते हैं चीन में बहुत ज्यादा डिमांड है स्टील की, उसकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और इसलिए स्टील की इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई, कॉपर की भी बढ़ गई। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीजें बढ़ रही हैं, तो उसकी रोकथाम आपने अपने देश में क्या की, उसके बारे में क्या प्रबंधन किया। यही तो सवाल उठता है कि अगर आपको मुद्रा विस्तार रखना है तो आप इस बात पर ध्यान रखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि दुनियां में क्या हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधान जी ने यह कहा था जो कुछ दुनियां में हो रहा है उससे हम अपने को अलग नहीं रख सकते। ठीक बात है। आप एक वैश्वीकृत व्यवस्था के अंग बन गए हैं। दुनियां में जो रहा है उसका परिणाम आप पर पड़ता है। लेकिन यह क्या बात है कि दुनियां में जो कुछ महंगाई का है, उसका तो परिणाम हमारे ऊपर पड़ता है लेकिन जो कुछ दुनिया में समृद्धि का है, उसका परिणाम हमारे ऊपर नहीं पड़ता? अगर हम दुनियां से मिले-जुले हैं तो हमारी समृद्धि की रफ्तार भी वही होनी चाहिए, जिस रूप में महंगाई से प्रभावित होते हैं, इंफ्लेशन से प्रभावित होते हैं, तो फिर उसी रफ्तार में हम समृद्धि में क्यों नहीं प्रभावित होते। अगर समृद्धि भी उसी हिसाब से बढ़े तो फिर संतुलन हो जाएगा, लोगों पर बोझ कम पड़ेगा और पास में आर्थिक शक्ति होगी। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि आपने उसकी क्या व्यवस्था की है। फिर आपने एक बात रखी कि हमारे देश में इस बार मानसून 13 परसेंट डेफिसेंट था और इसलिए अनाज के दाम बढ़ने स्वाभाविक थे। फिर आप यह भी कहते हैं कि मगर आप आशान्वित हैं कि अगली फसल ठीक हो जाएगी, यह 13 परसेंट की जो मानसून में कमी थी वह आने वाले महीनों में पूरी हो जाएगी और शायद इसकी वजह से रबी की फसल हमें पूरा कर देगी। मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई थी कि आपके माननीय कृषि मंत्री जी ने भी इसी आशय की बात कही। मगर यह तो बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है। क्या यह आपके हाथ में है जैसे पेट्रोफ्लेशन आपके हाथ में नही है, वैसे ही मानसून आपके हाथ में नहीं है। आपके क्या दुनिया के किसी देश के हाथ में नहीं है। अभी तक कोई ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया, जहां तक थोड़ा बहुत विज्ञान मैं जानता हूं, नहीं हुई है, जो यह बता दे कि अगर 13 परसेंट की डेफीशिएंसी इधर हुई है तो, अगले महीनों में हम 13 परसेंट पूरा करे लेंगे, अभी ऐसा हुआ नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारा मानसून पर अगर किसी दिन नियंत्रण आ जाएगा तो शायद दुनिया में बहुत सारी कठिनाइयां अन्नोत्पादन की दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इस प्रकार वह भी आप आशा पर ही केन्द्रित हैं। फिर आप पेट्रोफ्लेशन के मामले में भी आशा पर ही केन्द्रित हैं। मैटल, स्टील और कोल इत्यादि के जो अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ रहे हैं, वे भी आपके हाथ में नहीं हैं। फिर आप यह आश्वासन कैसे देते हैं कि आपकी ग्रोथ रेट 8 परसेंट होगी, 7 परसेंट होगी या 6 परसेंट होगी। मुझे तो उसमें भी संभावना नजर नहीं आती कि आपने पहले जो वचन दिया था कि सात से आठ परसेंट तक आप रखेंगे, अब आपने

कहा कि शायद 6 परसेंट तक रखेंगे, लेकिन वह भी आप रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे इसमें कठिनाई नजर आती है। अगर आप वह भी नहीं रख पाए तो फिर महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि फिर उसके लिए जो वित्तीय प्रबंधन आपको करने होंगे, वे सब inflationary होंगे। फिर आपने एक बात यह भी कही कि यह liquidity management, short sighted liquidity management की वजह से हुआ है। अब जरा इन चारों बातों पर एक-एक करके गहराई से देख लें। सबसे पहले पैट्रोफ्लेशन है। अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े। इसके लांग टर्म सबमिशंस तो आज देने से कोई फायदा नहीं है कि आप नए स्रोत खोलिए। खोलने ही पढ़ेंगे, खोजने ही पढ़ेंगे। नए समझौते कीजिए। रूस से समझौते कीजिए, गैस हाइड्रेट्स हमारे देश में बहुत हैं, हमारे समुद्रों में हैं, उनको निकालिए। हमारे यहां जो कुछ नए-नए तेल के स्थान मिलें हैं, उनमें जल्दी जल्दी एक्सप्लोरेशन शुरू कराइए। ये जल्दी होने वाली बातें नहीं हैं। तात्कालिक मंहगाई को रोकने में इनका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जरूरी होगा कि आप इस तरफ आगे बढ़ें, किन्तु आप ऐसा आज तो नहीं कर सकते। फिर पैट्रोफ्लेशन में एक चीज़ है, गैस के दाम। उसके बारे में देश आपसे एक बात जानना चाहता है कि लगभग 90 प्रतिशत गैस का आप अपने ही देश में उत्पादन करते हैं और केवल दस प्रतिशत गैस आप आज आयात करते हैं। आपके पैट्रोलियम मिनिस्टर का ही यह बयान है। सरकार ने सदन में यह बयान दिया है। मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें आंकड़े क्या हैं। 9 प्वाइंट कुछ मिलियन टन आपकी आवश्यकता है जिसमें से सात प्वाइंट कुछ आप इसी देश में पैदा कर रहे हैं और करीब 10 प्वाइंट कुछ आप बाहर से मंगा रहे हैं। इस प्रकार से आप अपने देश में केवल 10 प्रतिशत गैस बाहर से आयात करते हैं और 90 प्रतिशत यहीं पैदा करते हैं। अगर कोशिश की जाए और नज़दीक से गैस लाने की कोशिश की जाए तो आयात का दाम भी कम होगा। इसके अतिरिक्त देश में जो गैस के नए भंडार मिले हैं, उन्हें अगर आप देखेंगे तो गैस की आवश्यकता की पूर्ति हम कर सकते हैं। या तो ये आंकड़े गलत हैं जो सरकार कहती है कि हम 90 प्रतिशत यहां प्रोड्यूस कर रहें हैं और केवल 10 प्रतिशत आयात कर रहे हैं। अगर ये आंकड़े सही हैं तो फिर गैस के दाम इतनी मात्रा में बढ़ना गलत है। उस 90 परसेंट का दाम भी आप इम्पोर्टेड गैस के आधार पर ही दे रहें हैं। क्योंकि आपने इम्पोर्ट प्राइस पैरिटी रखी हुई है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर स्पष्ट स्थिति क्या है, यह हम जानना चाहेंगे कि यह क्या हो रहा है? गैस के बारे में अभी मैंने पढ़ा और मुझे जानकर बहुत चिंता हुई कि आपने जो अपना आर्थिक विश्लेषण रखा है, उसमें आपने यह सुझाव दिया है कि गैस हाइली सब्सीडाइज्ड है और इसकी सब्सिडी आपको कम करनी है यानी गैस का दाम और बढ़ाना है। पिछले दिनों हमारे पैट्रोलियम मिनिस्टर ने भी इसी तरह की बातें कही थीं कि देखिए, पाकिस्तान में गैस का दाम 490 रुपए है, फलां जगह 400 रुपए है, कहीं 380 रुपए है और यहां तो हम दो सौ कुछ रुपए में ही दे रहे हैं। उसी समय मुझे शंका हो गयी थी कि गैस के दाम और बढ़ाए जाने की कोशिश हो रही है। महोदया, अब गैस का दाम अगर बढ़ेगा

1.00 P.M.

तो आपसे मिलने आने वाले परिवारों का बजट किधर जाएगा, महंगाई किधर जाएगी, यह देखने की बात है। यह तर्क दिया जा रहा है कि यह इसलिए बढ़ाना जरूरी है क्योंकि गैस को जो सब्सिडी दी जा रही है वह सब्सिडी...

श्री जय राम रमेश (आंध्र प्रदेश): मैडम, यह शॉर्ट ड्यूरेशन है या लाँग ड्यूरेशन?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): जोशी जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि एक बज गया है। आप कितना और समय लेंगे ताकि आपके भाषण की समाप्ति के बाद ही मैं सदन को भोजनावकाश के लिए स्थगित कर सकूं?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मैडम, यह मंहगाई का विषय है और मैं समझता हूं कि इस पर आप समय की महंगाई न करें।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): समय की कीमत का भी ध्यान रखिए।

एक माननीय सदस्य: समय महंगा हो गया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): जो यहां पर पीठासीन अधिकारी थे, उनके साथ यह तय हो गया था कि जब तक जोशी जी बोलेंगे तब तक हाउस चलेगा, उसके बाद हम लंच के लिए एडजोर्न करेंगे। हमारी पार्टी का समय है और हमारे पहले स्पीकर बोल रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): मैंने यह नहीं कहा है, मैंने सिर्फ यह कहा है कि कितना समय लेंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज: कितने समय का कोई अर्थ नहीं है। आप उनको बोलने दीजिए। यह हमारे समय से ज्यादा समय नहीं लेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): मुझे सदन की राय भी लेनी है क्योंकि भोजनावकाश का समय है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: इस पर सदन की राय नहीं, पीठासीन अधिकारी ने निर्णय कर लिया था। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): He has to speak within the allotted time. ..*(Interruptions)*...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Yes, we are aware ...*(Interruptions)*... हम अपने टाइम से ज्यादा समय नहीं लेंगे। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): ये यह कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: उपसभाध्यक्ष जी, मेरा ...(व्यवधान)...

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): The hon. Member can speak for as long as he wishes. But I think what the Chair wants to know is when should we adjourn for lunch and then resume ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: As soon as I finish, we will adjourn for lunch ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: That's fine. That's all she is asking.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Mr. Minister, it was decided that we will adjourned for lunch after he finishes his speech ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: That is what she wants to know... *(Interruptions)*... Anyway, let him speak ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): चूंकि यह पहले से ही निर्धारित हो गया था कि जब तक जोशी जी बोलेंगे तब तक हाउस चलेगा, इसलिए ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): मैडम, लंच के बाद कराइए। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): अब आप जोशी जी पर निर्भर हैं ...(व्यवधान)... जब वे खत्म करें तभी आपका भोजनावकाश का ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: यदि आप जोशी जी पर निर्भर करेंगी तो देश की मंहगाई भी ठीक हो जाएगी और साथ ही बहुत सी व्यवस्थाएं भी ठीक हो जाएंगी।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): वह तो जनता तय करेगी।...(व्यवधान)...

AN HON. MEMBER: Madam, we can resume the discussion after lunch ...*(Interruptions)*... Let us...*(Interruptions)*...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब हम यहां एक-चीज पर विचार कर रहे हैं...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): जोशी जी, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि आपके लिए निर्धारित समय 30 मिनट है और आप 29 मिनट का समय ले चुके हैं। इससे माननीय सदस्य भी आश्वस्त होंगे।...(व्यवधान)... चूंकि जब सभापति जी थे तब आपने यह निर्णय ले लिया था इसीलिए मैं उसी आदेश का पालन करूंगी।...(व्यवधान)... और जोशी जी से निवेदन करूंगी। ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी को भी, इसी में सुविधा होगी कि एक

बार यह जो कुछ निवेदन करना है...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): ठीक है।

श्री नीलोत्पल बसु: मैडम, मुझे एक सवाल पूछना है कि सुषमा जी ने सही आग्रह किया है कि वह आउटर लिमिट होगा, बीजेपी के पास जितना टोटल टाइम उपलब्ध था। आपने अभी-अभी प्वाइंट आउट किया है कि पूरा टाइम हो चुका है। इसलिए अभी ये जितनी देर बोलेंगे, वह चेयर की कृपा से बोलेंगे ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: जो आप कह रही हैं कि पूरा टाइम हो चुका है, इसको आप ढ़ाई घंटे के हिसाब से बांट रही हैं। चर्चा के लिए चार घंटे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): यह देखिए, चर्चा में जोशी जी के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित है। उन्होंने 29 मिनट का समय ले लिया है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: चार घंटे की चर्चा है, जिसमें हमें 45 मिनट तो वैसे ही मिलते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): आपने और नाम दिए हैं तो मैं ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह ढ़ाई घंटे की चर्चा नहीं है, चार घंटे की चर्चा है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): अच्छा आप जोशी जी की बात सुन लीजिए ताकि जल्दी से खत्म कर सकें।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: हम माननीय पीठासीन अधिकारी जी के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं ...(व्यवधान)... तब पता लगेगा कि वे आपके कथन से सहमत हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह चार घंटे की चर्चा है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: बहरहाल आप जितना यह समय ले रहे हैं, यह मेरे समय में नहीं देना चाहिए। ...(व्यवधान)... तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि पहले पैट्रोफ्लेशन के बारे में गहराई से विचार किया जाए। इसमें जो गैस का दाम है और जो आगे गैस के दाम बढ़ाने का विचार है, यह महंगाई को रोकने का विचार है या बढ़ाने का विचार है? मुझे उसमें एक तरफ देखकर यह आश्चर्य हुआ, यह कहा जा रहा है कि गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि अभी भी गांव और शहरों में एक प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो यह हमारी गैस आपूर्ति न करने की क्षमता को बताया जा रहा है या उस आदमी की गरीबी को बताया जा रहा है या जबर्दस्ती गैस का दाम बढ़ाने के लिए कोई बहाना ढूंढा जा रहा है? अगर उस आम आदमी के पास पैसा होता जिसके साथ आप अपना हाथ देने के लिए चुने गए थे, तो वह गैस

का प्रयोग करता। यदि आप यह कहेंगे कि वह गैस का प्रयोग नहीं कर पाता है और वह लकड़ी का प्रयोग कर रहा है तो आप डिफॉरेस्टेशन की वकालत करेंगे। यदि 30-35 प्रतिशत लोग लकड़ी पर निर्भर करते है तो लकड़ी कहां से आएगी? वह जंगल से आएगी, तो फिर आप एक तरह से जंगल काटने का समर्थन कर रहे हैं। इस बात को गहराई से ध्यान में रखना चाहिए। हमारी नीति यह होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास गैस पहुंचे। इससे जीवन की क्वालिटी भी बढ़ती है, जंगल का बचाव भी होता है और इससे प्रदूषण भी नहीं होता है। बजाए इसके कि हम गैस का उत्पादन करें और सस्ती गैस उपलब्ध कराएं, बल्कि इसके विपरीत हम तर्क यह दे रहे हैं कि हम आदमी के पास गैस नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए हम उसकी सब्सिडी घटा रहे हैं। यह तर्क मेरी समझ में आ रहा है। यह कुप्रबंधन है, टोटल मिसमैनेजमेंट है, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि ऐसी नीतियों का कदापि समर्थन न किया जाए, जो आम आदमी के हितों पर चोट पहुंचाती हैं। यह पेट्रोफिलेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़ रहे हैं। आज ही हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बताया कि कितने अधिक दाम पर हमें खरीदना पड़ेगा। क्या यह जरूरी नहीं हो जाता कि हम अपने एक्सचेंज रेट के बारे में पुनर्विचार करें? यह एक्सचेंज रेट, जो रुपए और डॉलर के साथ नत्थी है, क्या इस पर विचार करना जरूरी नहीं होगा? क्या जरूरी है कि रुपया कमजोर ही बना रहना चाहिए? क्या रुपया मजबूत नहीं होना चाहिए? क्या आप प्राइस पर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से रुपए का पुनर्मूल्यन करने का विचार करेंगे, जिससे कम से कम आप पर यह जो बोझ पड़ रहा है, यह बोझ कुछ कम हो? हम किस हद तक ऊपर जा सकते हैं? मैं यह नहीं कहता कि आप तत्काल वहां पहुंच जाएं, जहां अंतराष्ट्रीय स्तर पर रुपए का मूल्य होना चाहिए, मैं उसकी कठिनाइयों से वाकिफ हूं, लेकिन क्या रुपए को निरंतर कमजोर बनाए रखना जरूरी है? क्या रुपए को थोड़ा मजबूत नहीं किया जा सकता? क्या थोड़ा बोझ और कम नहीं किया जा सकता? मैं प्रबंधन की बात कर रहा हूं, मुद्राओं के प्रबंधन की, मौद्रिक प्रबंधन की बात कर रहा हूं। अगर यह इन्फ्लेशन इसी तरह से बढ़ता रहा तो अनेक प्रकार के संकट पैदा हो जाएंगे।

अभी आपने लिक्विडिटी की बात कही। आपने कहा कि पिछली सरकार ने थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़ा दी थी। यह 14% या 15% के पास होनी चाहिए थी, जबकि आपकी हो गई 16.7%। इसके बाद भी क्या हुआ? इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी, वह लिक्विडिटी हमने ऑब्जर्व कर ली। यह प्रबंधन है। लिक्विडिटी थोड़ी सी बढ़ी तो उसे हमने प्रबंधन करके, मैंने आपको आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि जैसे ही जनवरी में थोड़ी बढ़नी शुरू हुई, हमने उसे तुरंत कंट्रोल कर लिया, नियमित कर लिया। जब हम आपको मई के महीने में देकर गए थे तो बहुत अच्छी व्यवस्था देकर गए थे। एक बहुत ही अच्छा स्टेबल इन्फ्लेशन घटने वाला रेट देकर गए थे, लेकिन आपने उसे बढ़ा दिया। अगर हमने लिक्विडिटी बढ़ाई थी तो उसके फल हमें जितने भोगने चाहिए थे, वे हमें वहां मिलते। वे तो हमें वहां मिले नहीं, हमने उसे ठीक रखा, परंतु आप उस थोड़ी सी लिक्विडिटी से परेशान हैं। आपकी जो लिक्विडिटी है

उसकी हालत क्या है? आप कहते हैं कि 14% या 15% होनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री के लिए है 47% । बाकी के लिए आप कहते हैं 14% होगी। इसका अर्थ यह है कि अगर ओवर ऑल 14% है और इंडस्ट्री के लिए 47% है तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां तक पहुंचा ही नहीं गया है। होता यह है कि जब भी इन्फ्लेशन होगा, वह मोनिटरी मिसमैनेजमेंट की वजह से होगा। आप कहते हैं कि आपकी सेविंग्स की तुलना में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई। ठीक है। एम थ्री बढ़ गया, यह भी आप कहते हैं। लेकिन अगर आप एम थ्री को दुनिया के तमाम देशों की तुलना में देखें के इसकी क्या स्थिति है तो पाएंगे भारत की स्थिति बहुत ही अलग है। यू॰एस॰ए॰ में इंडस्ट्रियल सैक्टर में एम थ्री 170% है और टोटल का अनुमान है कि यह लगभग 300% है, चाइना में 200% है, मैंने बताया कि भारत में एम थ्री इंडस्ट्रियल सैक्टर के लिए 47% और ओवर आल आप 14% या 15% रखना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि बाकी जगह बहुत स्केयरसिटी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? एम थ्री का मिसमैनेजमेंट है। जहां एम थ्री पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच रही है और जहां नहीं पहुंचनी चाहिए, वहां ज्यादा पहुंच रही है। जब भी ऐसा होगा कि एम थ्री वहां पहुंचेगा, जहां नहीं पहुंचना चाहिए और वहां नहीं पहुंचेगा, जहां पहुंचना चाहिए तो इससे भारी असंतुलन होगा। इससे प्राइसेस काफी मात्रा में बढ़ेंगे, यह अर्थशास्त्र का सामान्य सा सिद्धांत है। आप जिस लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, उस लिक्विडिटी के मैनेजमेंट को भी देखिए। मैंने एक स्थान पर यह बात कही तो हमारे एक प्रतिष्ठित मंत्री जी ने कहा कि हमारा अमरीका से क्या मुकाबला? यह तर्क ठीक नहीं है कि अमरीका से हमारा क्या मुकाबला। हमारा मुकाबला सारी दुनिया से है। हम सारी दुनिया के साथ खड़े हैं, हम विश्व की महाशक्ति बनने की बात कर रहे हैं, 2020 तक हम कहीं जाना चाहते हैं। हमें मुकाबला करना है, हमें मुकाबले से डरना नहीं है। हमें अपनी इस अर्थव्यवस्था के प्रबंधन को बिल्कुल दुरुस्त करना है। अगर आपने नहीं किया तो एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो जाएगा। यह जो पेट्रोफि्लेशन है, इससे हमारी एनर्जी के बारे में, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह केवल पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स का ही सवाल नहीं है, इसमें फिर बिजली का सवाल आता है, इसमें फिर उन तमाम चीजों का सवाल आता है, जो हमारे देश के लिए उपयागी हैं, इसमें फिर दवाइयों का सवाल आता है। वर्ष 2005 में दवाइयां, कपड़े, इन सबका क्या होगा, इससे आप मेरे से अधिक परिचित हैं। इस तरह यह महंगाई आप रोक नहीं सकेंगे और इस एनर्जी सिक्योरिटी पर भारी सवाल आकर खड़े हो जाएंगे। आज भी देश में ऐसे स्थान हैं, जहां ऊर्जा नहीं मिल रही है। आपने कहा था कि सबको बिजली मिलेगी, लेकिन ऐसे राज्य हैं, ऐसे स्थान हैं, ऐसे नगर हैं, जहां पर बिजली जाती ज्यादा है और आती कम है। केवल बिजली ही नहीं, ऊर्जा के जितने भी प्रकार हैं, अगर आप उनकी सिक्योरिटी का, उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे तो देश की प्रतिरक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा, इकनॉमिक सिक्योरिटी पर भी इसका असर पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी पर भी इसका असर पड़ेगा। यह केवल छोटा सवाल नहीं है, तात्कालिक सवाल नहीं है कि थोड़े से दाम बढ़ गए और उस पर हमने

बहस कर ली। यह cascading effect केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं रहेगा, यह अनाज के क्षेत्र में जाएगा, यह दवाइयों के क्षेत्र में जाएगा, यह प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जाएगा और कुल मिलाकर सारे देश की सुरक्षा के लिए भी संकट पैदा करेगा। इससे आर्थिक सुरक्षा, प्रतिरक्षा की दृढ़ता, अन्न की सुरक्षा, ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। इसलिए जब आप इसको एक छोटे पैमाने पर देखते हैं, छोटे कैनवास पर देखते हैं और यह समझते हैं कि यह फौरी सवाल है, महीने-दो महीने का सवाल है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देश इस बात को देख रहा है कि पिछले अनेक वर्षों से, कई दशकों से हम इस पीड़ा को भुगत रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, अन्न-व्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्था, इन सब पर संकट है और जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में हम लोग घिरे हुए हैं, उसमें मैं नहीं मानता कि अगर आप इसका mis-manage करेंगे, तो इससे हम देश का ज्यादा हित कर सकेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस ओर पूरा ध्यान दें।

महोदया, आज की यह बहस मौद्रिक प्रबंधन के बारे में नहीं है, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि सदन इस बारे में गंभीरता से चर्चा करे कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों अमरीकी डॉलर के साथ चिपकी, क्यों यह जरूरी है कि हम अपने सारे फॉरेन एक्सचेंज को अमरीका में पार्क करें, क्यों हमारा रिज़र्व बैंक उसको पार्क नहीं कर सकता? ये सवालात हैं, जिनका जवाब हमें ढूंढना है और उस फॉरेन एक्सचेंज से हमारा जो asset है, हम देश के हित में, उसका कितना उपयोग कर रहे हैं और अन्य अर्थव्यवस्थाएं उसका कितना फायदा उठा रही हैं, ये सवाल भी इसके साथ, यानी management of economy से जुड़े हुए हैं। आज इस पर चर्चा का दिन नहीं है, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि इस गंभीर विषय पर सदन चर्चा करे। आज संपूर्ण मौद्रिक प्रबंधन को एक नया आयाम देने की जरूरत है और इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार ने पिछले 6 महीनों में जिस प्रकार से आर्थिक कुप्रबंधन किया है, economic mis-management किया है, यह उसका नतीजा है कि दाम बढ़ रहे हैं और मुझे यह कहने में डर लग रहा है कि अगर यही हाल रहा, तो यह inflation 7 पर नहीं रूकेगा, यह 8, साढ़े आठ, नौ, दस, पता नहीं कहां तक जाएगा। एक बार मैंने शायद अगस्त महीने की शुरुआत में ही जसवंत सिंह जी से कहा था कि यह inflation शायद 9 या 10 प्रतिशत तक जा रहा है, तो वे कहने लगे कि ऐसी भाषा मत बोलिए। मैंने कहा कि मैं बोलूं या न बोलूं, जो स्थिति है, वह तो यही है और तत्काल ही वह 9 प्रतिशत के करीब पहुंच गया था। तो यह स्थिति है। अगर आपने निश्चितता के साथ, दृढ़ता के साथ, दूरदृष्टि के साथ, इसका प्रबंध नहीं किया, तो इसका समाधान नहीं होगा। यह सिर्फ भिंडी और करेले के भाव का मामला नहीं है, यह देश की सुरक्षा, देश के भविष्य, देश की आर्थिक स्थिति, देश की खाद्य संबंधी, ऊर्जा संबंधी, देश की प्रतिरक्षा संबंधी सारी समस्याओं से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए मैं आज इतना ही कर सकता हूं कि मैं आज भगवान से प्रार्थना करूं कि वित्त मंत्री जी, Thiruvalluvar को और पढ़ें और उनके संदेश के आधार पर, भगवान आपको अर्थव्यवस्था को ठीक, सुप्रबंधित

करने की शक्ति प्रदान करे। मैं आज यही कह सकता हूं। मुझे पता नहीं, भगवान का नाम सुनकर आपके सहयोगियों को क्या दिक्कत होगी ...(व्यवधान) आप इस प्रबंधन की ओर बढ़ें। मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करुंगा कि ... (व्यवधान)

श्री नीलोत्पल बसु: भगवान ने यह जिम्मेदारी आप लोगों को दे रखी है ...भगवान कितने लोगों की जिम्मेदारी लेंगे?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मेरा तो केवल इतना कहना है कि भगवान आपको भी सद्‌बुद्धि दे ...मुझे मालूम है कि भगवान का नाम लेने से आपको तकलीफ नहीं होगी, मगर आपके सहयोगियों को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी ...(व्यवधान)... मैं भगवान से यह प्रार्थना करूंगा कि ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, अगर एक मिनट यील्ड करें, सर ...(व्यवधान)... I was just asking भगवान ने अगर बी॰जे॰पी॰ को पहचान लिया तो फिर इनको कैसे पहचानेंगे? ...(व्यवधान)...

डा. मुरली मनोहर जोशी: भगवान आपको ऐसी सामर्थ्य दें कि आप इसे ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ सकें और देश को इन खतरों से बचाने की तरफ आगे बढ़ें और अगर आप ईमानदारी से इस तरफ बढ़ेंगे तो हम इसमें आपका सहयोग करेंगे कि देश की प्रतिरक्षा को, देश की सुरक्षा को, देश की ऊर्जा को, देश की खाद्य व्यवस्था को हम ठीक कर सकें। लेकिन अगर आपने इसमें किसी प्रकार की भी ढील-ढाल की या निहित स्वार्थों का साधन किया तो मुझे बहुत विनम्रता के साथ कहना पड़ता है कि हम इसका हर जनतांत्रिक तरीके से डट कर विरोध करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): धन्यवाद, जोशी जी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at sixteen minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at sixteen minutes past two of the clock.

[MR. CHAIRMAN in the Chair.]

श्री जय राम रमेश : सर, लाइव टैलीकास्ट का कुछ असर नहीं हुआ।

श्री सभापति: अभी तो शुरू हुआ है। उस का रिएक्शन आने दीजिए।

श्री जय राम रमेश: एक फतवा जारी करवा दीजिए।

श्री सभापति: जोशी जी, आप बोलेंगे ? जोशी जी को किसी मीटिंग में जाना है, इसलिए उन्हें बुलवा रहा हूं। जोशी जी, आप 5 मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

श्री शरद अनंत राव जोशी (महाराष्ट्र): सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आज एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं आभारी हूं कि आप ने मुझे पहले बोलने का समय दिया । मैं 5 मिनट ही बोलना चाहता हूं और मेरा बोलना, इसलिए महत्व की बात समझता हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र भारत पार्टी का सदस्य हूं, जोकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की स्वतंत्र पार्टी की वारिसदार है।

सभापति जी, हम आर्थिक सुधार को मानते हैं और आर्थिक सुधार के लिए मानवीय चेहरे की जरूरत इसलिए नहीं समझते क्योंकि आर्थिक सुधार से अधिक मानवीय और अधिक दयालु कुछ नहीं होता है। सभापति जी, कीमतों के सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं । कई दिनों से मैं यह सुनता आ रहा हूं कोई भी विषय हो तो यह पूछा जाता है कि पिछले 4 सालों में आप ने क्या किया और हम ने क्या किया। आप को हमारे दोष निकालने का कोई अधिकार नहीं बनता। कम-से-कम कीमतों के बारे में मुझे अच्छा लग रहा है और मैं कह सकता हूं कि इस तरह के विवाद की कोई जगह नहीं है क्योंकि बजट के पूर्व जो इकॉनोमिक सर्वे पेश किया गया था, उस से बिल्कुल स्पष्ट है कि पहली सरकार ने इस सरकार के हाथ में जब व्यवस्था दी, तब इस तरह की कीमत बढ़ाने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। अब जो कुछ हुआ है, वह इन 6 महीनों में हुआ है। वित्त मंत्री जी ने जब बजट पेश किया तो सब तरफ से यह आलोचना हुई थी कि इस से कीमतें बढ़ने वाली हैं। इससे टैक्सेशन का संबंध था, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह स्पष्ट है कि बजट इनफ्लेशनरी होगा, इस का डर था। अब इस तरह से हो रहा है। मैं यह कहूंगा कि पिछले 5 सालों में एक आर्थिक डिसिप्लिन का वातावरण आ गया था कि Now, we are in a state where we are populist, permissive and therefore inflationary.

वित्त मंत्री जी, अभी मैंने दीवाली के समय दुकानों में देखा कि सोने की दुकानों में खरीद करने वाले सारे-के-सारे शासकीय नौकर थे, बाकी कोई दूसरा खरीदने नहीं जा रहा था। हां, मजदूरों की बस्तियों में जाने वालों की अलग दुकान होती है और वहां भी खरीद होती है, लेकिन नौकरदारों को छोड़कर किसी ने दीवाली नहीं मनायी।

सभापति जी, अभी मुरली मनोहर जोशी जी ने यह कहा कि सब्जियां महंगी हो रही हैं, इसलिए मैं एक विशेष स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। अगर फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं तो उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। उसके कारण शहर में जिस तरह के चलन की वृद्धि हो रही है या ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में आ रहा है, इससे किसानों को मिलने वाली कीमतें और ग्राहक को जो कीमतें देनी पड़ती हैं, उसमें जो दरार होता है, वह बढ़ गया है। अगर मैं यह कहूं कि यह कीमत वृद्धि मुझे बहुत ही खतरनाक दिखाई देती है, तो गलत नहीं होगा। इसलिए कि एक पेट्रॉलियम की

चीजें छोड़ी जायें तो सारी दुनिया में अब रिसेशन है खास कर खेती की उपज के बारे में सारी जगह कीमतें कम हो गई हैं। उसके बावजूद हिन्दुस्तान में तो कीमतें बढ़ रही हैं, जोकि मुझे अब और भी ज्यादा खतरनाक लगता है। हिन्दुस्तान में डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, इसलिए रुपये की कीमत बढ़ रही है। रुपये की कीमत बढ़ रही है इसलिए नहीं कि हमारी ताकत बढ़ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक मौका मिला था कि इस मौके का फायदा उठाकर हम एक्सपोर्ट बढ़ाते, तो हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा ताकतवर हो सकती थी। थोड़े में सभापति जी, मुझे लगता है कि नई यू॰पी॰ए॰ सरकार की जो आर्थिक प्रवृत्ति है, एक आर्थिक दर्शन है, मानवीय चेहरा देने का, उसके कारण आर्थिक शिष्ट जो है, वह डिस्प्लिन नहीं रहा है और इसी के कारण लोगों को खुश करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उनको लगता है कि चलो, हम चुनाव जीतकर आये हैं, अब जितने लोगों को ज्यादा खुश करेंगे, उतना अच्छा रहेगा, लेकिन यह सारे हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सभापति जी, आपने पांच मिनट दिये, मैंने पांच मिनट में पूरा किया, धन्यवाद।

श्री सभापति: स्टेट मिनिस्टर, रेलवे, श्रीनारनभाई रठवा, रेलवे का जो एक्सिडेंट हुआ है, उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। बोलिए।

INFORMATION TO THE HOUSE

Railway accident in Hoshiarpur district of Punjab

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नारनभाई रठवा): सभापति महोदय, रेल दुर्घटना विवरण आज दिनांक 14 दिसंबर, 2004 को जालंधर से पठानकोट जा रही पैसेंजर ट्रेन का जम्मू-तवी एक्सप्रेस से करीब 12 बजे टकराव हो गया। जॉलंधर -पठानकोट पैसेंजर का एक डिब्बा उलट गया तथा जम्मू-तवी एक्सप्रेस का इंजन तथा एक डिब्बा पटरी से उतर गए। घटनास्थल जालंधर-पठानकोट सेक्शन के भंगाला एवं मृथला स्टेशन के बीच में है। यह स्थान रेलवे के फिरोजपुर मंडल में है एवं पंजाब के होशियारपुर जिले में आता है। ऐसी सभावना है कि इस दुर्घटना में लगभग 25 पैसेंजरों की मृत्यु हुई (व्यवधान) एवं लगभग 30 पैसेंजरों के घायल होने की आशंका है। पठानकोट एवं अमृतसर से मेडिकल रिलीफ वैन भेज दी गयी है। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है और रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी स्वयं बोर्ड के कुछ सदस्यों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं।